अधिनियम, 1979, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 आदि। संबंधित कल्याण निधियों के अंतर्गत शुरू किए गए कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और अभ्रक खानों, सिनेमा उद्योग तथा बीडी उद्योग में लगे कर्मकारों को भी शामिल किया जाता है। राज्य सरकारों ने भी हथकरघा बुनकरों, रिक्शा चालकों आदि जैसे विशिष्ट कार्यकलापों में लगे कर्मकारों की बड़ी संख्या को शामिल करके बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी प्रारम्भ की हैं। असंगठित कामगारों के नियोजन की गुणवता और कार्यपरिस्थितियों में सुधार, किया जाना सरकार के लिए महत्वपूर्ण चिन्ता का विषय बना हुआ है।

जहां तक नए सिरे से नीतिगत पहलों का संबंध है, केन्द्रीय सरकार ने असंगठित कामगारों को नियोजित करने वाले कृषि क्षेत्र के पश्चात् दूसरे सबसे बड़े एकल कार्यकलाप वाले निर्माण उद्योग में लगे कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया है। सरकार का यह भी प्रयास रहा है कि मौजूदा उपायों का संवर्धन किया जाए और कल्याणकारी उपायों का प्रावधान किया जाए तथा विधायी संरक्षण को असंगठित क्षेत्र के अधिक से अधिक कर्मकारों पर लागू किया जाए।

Decision to lease coal mines

*477. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision to lease coal mines in Australia to ensure a regular supply of coal; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise in view of answer to part (a) of the question.

Reversing sharp fall in Exports

*478. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether he has asked the banks and trade bodies to draw up a joint strategy to reverse the sharp 17% fall in exports to East Asia in 1997-98 and step up investments;

(b) if so, whether any guidelines have been issued for liberalisation of credit facilities; and

(c) what are the other measures being adopted to boost exports?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) to (c) In view of the situation arising out of the financial and currency turmoil in some of the Fast Asian countries, meeting was convened under the Chairmanship of the Commerce Minister on 17.6.98 with the representatives of RBI, financial institutions and Chambers of Commerce. In this meeting, it was observed that our exporters and industrialists should take appropriate steps to meet the new challenges and take advantage of the emerging opportunities in the East Asia and in order to acnieve the same, financial institutions, Exim Bank and ECGC may extend necessary support to the exporters and investors. It was also decided that a delegation consisting of representatives of trade, financial institutions and industry would visit identified East Asian countries to initiate a dialogue with their counterparts for formalising various institutional tie-ups.

कोयला कंपनियों में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के मामले

*479. **श्री रामदास अग्रवाल:**
श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान तथा अब तक, विभिन्न कोयला कंपनियों विशेषतया बी०सी०सी०एल०, सी०आई०एल०, डब्लू०सी०एल० तथा ई०सी०एल० में कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार तथा अन्य-अनियमितताओं के संबंध में सांसदों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) संसद सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों के संबंध में सरकार द्वारा अब तक किन-किन मामलों में कार्रवाई नहीं की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (घ) 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली विभिन्न कोयला कंपनियों में, विशेष रूप से बीसीसीएल, सीआईएल मुख्यालय, डब्लूसीएल, ईसीएल और सीआईएल की अन्य सहायक कंपनियों में हो रहे भ्रष्टाचार तथा अन्य अनियमितताओं और सतर्कता संबंधी कुप्रबंधन के संबंध में कोयला मंत्रालय में सांसदों से प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:—

	1995-96					1996-97					1997-98						जोड़
	बीसीसीएल	सीआईएल	डब्लूसीएल	ईसीएल	अन्य	बीसीसीएल	सीआईएल	डब्लूसीएल	ईसीएल	अन्य	बीसीसीएल	सीआईएल	डब्लूसीएल	ईसीएल	अन्य		
कोयला मंत्रालय में सांसदों से प्राप्त शिकायतों की संख्या	1	3	—	—	4	5	1	3	—	8	2	3	3	2	11		46
ऐसी शिकायतों की संख्या, जिन्हें जांच के लिए कंपनियों के सतर्कता विभाग को संदर्भगत किया गया है	1	3	—	—	4	5	1	3	—	8	2	3	3	2	11		46
प्राप्त की गई जांच-रिपोर्ट	1	3	—	—	2	4	—	1	—	7	—	2	1	—	2		23
कंपनियों में प्रतीक्षित जांच रिपोर्ट	—	—	—	—	2	1	1	2	—	1	2	1	2	2	9		23
ऐसे मामलों की संख्या, जिस पर कोयला मंत्रालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है तथा जिसके बारे में कोयला कंपनियों को सूचित कर दिया गया है एवं सांसदों को जवाब भेज दिए गए हैं।	1	3	—	—	2	4	—	1	—	7	—	2	1	—	2		23

उपर्युक्त विवरण में जुलाई, 1995 से जून, 1998 तक की अवधि अन्तर्ग्रस्त है।

किसी भी कर्मचारी पर लगाए गए आरोपों के प्रमाणित होने पर कोयला कंपनियों द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करनी पड़ती है। इसी प्रकार, उपर्युक्त मामलों में से एक मामले में सी०आई०एल० की सहायक कंपनी के एक बोर्ड-स्तर के अधिकारी के विरुद्ध कोयला मंत्रालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।

Winding up of PSUs

*480. DR. ALLADI P. RAJKUMAR:

Will the Minister of INUDSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have identified Public Sector Undertakings "which cannot be revived under any circumtances" and therefore, have to be disposed of;

(b) if so, the details of such PSUs and the modalities, if any, decided for their disposal; and

(c) the manner in which the interests of the workers are proposed to be protected?

*THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Govt. have announced a liberal and attractive voluntary retirement package.

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Production and Demand of Coal

3521. DR. ARUN KUMAR SARMA: *Will the Minister of COAL* be pleased to state:

(a) the details of the total production and demand of coal in the country during the the last five years, State-wise;

(b) the target fixed for production of coal during this period and Ninth Plan through open cast and udnerground mining process; and

(c) the amount of royalties being paid to different State Governments against various grades of coal?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY): (a) The demand for coal is not assessed State-wise. This is assessed industry/sector-wise for the country as a whole. The details of the total State-wise production (excluding TISCO/IISCO & DVC) and demand of coal in the country during the last five years are as under:—

PRODUCTION

State	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	(Prov) 1997-98
West Bengal	16.33	16.72	17.50	17.66	16.47
Bihar	68.82	68.08	68.87	71.34	75.08
Orissa	24.30	27.33	32.70	37.36	42.17
Madhya Pradesh	72.86	74.86	79.76	83.28	84.35
Maharashtra	20.45	21.07	22.82	24.86	26.24
Uttar Pradesh	12.14	13.82	14.80	15.40	15.86
Assam & N.E. States	1.20	1.19	0.82	0.75	0.69
Total (CIL)	216.10	223.07	237.27	250.65	260.68
Andhra Pradesh (SCCL)	25.21	25.65	26.77	28.70	28.94
Demand	268.80	268.50	298.00	325.00	323.38
	(6.00)	(5.00)	(6.70)	(2.70)	(6.80)